



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 16, 2006/फाल्गुन 25, 1927

No. 104]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2006/PHALGUNA 25, 1927

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2006

सा.का.नि. 162(अ).—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

- (i) इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2006 कहा जाए।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 3ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3ख. सेवानिवृत्ति के पश्चात् लाभ.—(1) एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अपने जीवनकाल में, एक अर्दली, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के एवज में भुगतान करने, अनुबंध आधार पर सचिवालयीय सेवा प्राप्त करने पर हुए खर्च को पूरा करने और एक कार्यालय-सह-आवास के रख-रखाव के लिए, प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपये का भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा। वह, निशुल्क आवासीय फोन तथा 1,500 निशुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली निशुल्क कॉलों के अलावा) का भी पात्र होगा।

(2) एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अपने जीवनकाल में, एक अर्दली पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए, चार हजार रुपए प्रतिमाह प्राप्त करने का पात्र होने के साथ-साथ निशुल्क आवासीय फोन तथा 1,500 निशुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली निशुल्क कॉलों के अलावा) का भी पात्र होगा।

(3) उप-नियम (1) तथा (2) में उल्लिखित सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे :

यह प्रावधान किया गया है कि इस नियम के तहत उपलब्ध सेवानिवृत्ति लाभ ऐसी आय नहीं मानी जाएगी जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर योग्य होती है।”

[फ्र. सं. एल-11017/2/2006-न्याय]

गार्गी मुकर्जी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी.—मुख्य नियम दिनांक 4 अगस्त, 1959 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), पृष्ठ 1161 [गृह मंत्रालय संख्या 15-6-58-न्यायिक-I] में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 1366 दिनांक 18-12-1974
2. सा.का.नि. 634 दिनांक 22-4-1976
3. सा.का.नि. 854 दिनांक 1-8-1980
4. सा.का.नि. 11769(अ) दिनांक 4-11-1986
5. सा.का.नि. 680(अ) दिनांक 12-11-1991
6. सा.का.नि. 381(अ) दिनांक 20-4-1993, दिनांक 25-9-1992 से लागू।
7. सा.का.नि. 444(अ) दिनांक 10-5-1995, दिनांक 12-11-1994 से लागू।
8. सा.का.नि. 717(अ) दिनांक 3-11-1995
9. सा.का.नि. 718(अ) दिनांक 3-11-1995, दिनांक 1-4-1994 से लागू।
10. सा.का.नि. 149(अ) दिनांक 24-2-1999
11. सा.का.नि. 393(अ) दिनांक 25-5-2001
12. सा.का.नि. 757(अ) दिनांक 4-10-2001, दिनांक 25-5-2001 से लागू।
13. सा.का.नि. 110(अ) दिनांक 5-2-2003
14. सा.का.नि. 202(अ) दिनांक 15-3-2004

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2006

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 23, read with Sub-section (2) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely :—

- (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, for rule 3B, the following rule shall be substituted, namely :—

“3B. Post retiral benefits.—(1) A retired Chief Justice shall be entitled during his life time to a payment of rupees twenty-five thousand per month for defraying the services of an orderly, driver and security guard, for meeting the expenses incurred towards secretarial assistance on contract basis and for maintainance of an office-cum-residence. He shall also be entitled to a residential telephone free of cost and the number of free calls to the extent of 1,500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities).

(2) A retired Judge shall be entitled during his lifetime to a payment of four thousand rupees per month for defraying the services of an orderly and also shall be entitled to a residential telephone free of cost and the number of free calls to the extent of 1,500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities).

(3) The retiral benefits mentioned in Sub-rules (1) and (2) shall be provided by the Registrar of the Supreme Court of India on furnishing a certificate by the retired Chief Justice and the Judge as the case may be in the form specified by the Registry of the Supreme Court of India:

Provided that the retiral benefits available under this rule shall not be deemed to be income, liable to tax, under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. L-11017/2/2006-Jus]

GARGI MUKERJEE, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 935, dated the 4th August, 1959, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), page 1161 [Ministry of Home Affairs F. No. 15-6-58-Judl-I] and subsequently amended by :—

1. G.S.R. 1366 dated 18-12-1974.
2. G.S.R. 634 dated 22-4-1976.
3. G.S.R. 854 dated 1-8-1980.
4. G.S.R. 11769(E) dated 4-11-1986.
5. G.S.R. 680(E) dated 12-11-1991.
6. G.S.R. 381(E) dated 20-4-1993 w.e.f. 25-9-1992.
7. G.S.R. 444(E) dated 10-5-1995 w.e.f. 12-11-1994.
8. G.S.R. 717(E) dated 3-11-1995.
9. G.S.R. 718(E) dated 3-11-1995 w.e.f. 1-4-1994.
10. G.S.R. 149(E) dated 24-2-1999.
11. G.S.R. 393(E) dated 25-5-2001.
12. G.S.R. 757(E) dated 4-10-2001 w.e.f. 25-5-2001.
13. G.S.R. 110(E) dated 5-2-2003.
14. G.S.R. 202(E) dated 15-3-2004.